ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

28 मार्च, 2018 • वर्ष 1, अंक 10

सात दिन – सात पृष्ठ

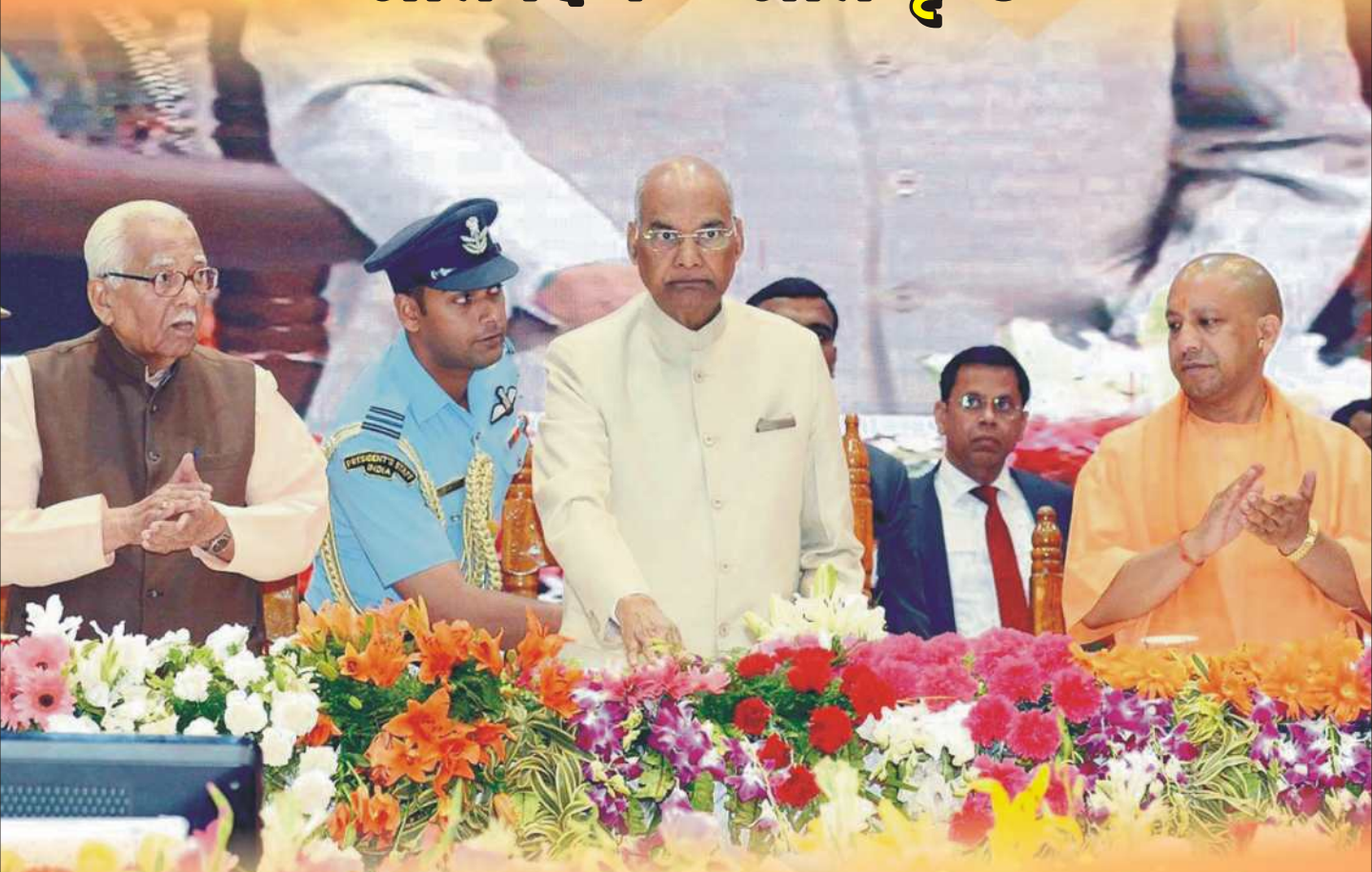

जनपद वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास के अवसर पर
महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

- वाराणसी को 3437 करोड़ रूपये की योजनाओं की सौगात
- 20 लाख युवाओं को मिलेंगे रोजगार • फिरोजाबाद के कांच उद्योग को बढ़ावा
- गोरखपुर को मिला नयी उड़ान का तोहफा • तीन वर्ष के लिए स्वीकृत हुई नई तबादला नीति

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

3437 करोड़ रूपये की योजनाओं की सौगात

महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने काशी को 3473 करोड़ रूपये की परियोजनाओं की सौगात दी। 2,118 करोड़ रुपये की लागत से एनएच–7 पर वाराणसी–हनुमना का निर्माण एवं पैकेज–3 के तहत 96.800 से 140.265 कि0मी0 तक चार लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन तथा 1,355 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वाराणसी रिंग रोड फेज–1 सहित कुल 3,473 करोड़ रुपये के लागत की परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद यहां के लोगों सहित आसपास के जिलों एवं प्रदेशों तक के लोगों को समस्या से निजात मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

कौशल विकास से खुला विकास का रास्ता

इस अवसर पर राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने कहा कि वर्ष 2025 तक विश्व में भारत सबसे बड़ा युवा देश हो जायेगा। कौशल विकास, स्टार्ट अप व स्टैन्डअप आदि योजनाओं के क्रियान्वयन से विकास का नया रास्ता खुल गया है।

उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गो के हो रहे निर्माण कार्य की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है।

स्प्रिचुअल सिटी के साथ स्मार्ट सिटी बन रहा वाराणसी

काशी अपनी सिप्रचुअल सिटी की पहचान के साथ ही अब स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। इस नगरी में प्राचीनता के साथ आधुनिकता को अपनाने की कला है। यहां वैदिक कर्मकांड और गंगा आरती के साथ ही बीएचयू, आईटीआई और अन्य संस्थानों की आधुनिकतम प्रयोगशालाओं में अनवरत शोध की प्रक्रिया संचालित हो रही है। व्यापार सुविधा केन्द्र के रूप में दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना काशी के विकास का नवीनतम उदाहरण है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविद जी ने भी अपने वाराणसी प्रवास के दौरान इस बदलाव को अनुभव किया और दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित समारोह में इसका वर्णन किया।

भूमिगत केबलिंग से बदली वाराणसी की तस्वीर

राष्ट्रपति ने वाराणसी के खुले एवं बिखरे बिजली तारों का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व कई बार उनका काशी आना हुआ तथा उस दौरान शहर में जगह–जगह बिजली के पोल व तार सड़क पर एक से दूसरी ओर गये होते थे, जिसे देखकर डर लगता था तथा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती थी। किन्तु केन्द्र सरकार की भूमिगत विद्युत केबलिंग योजना को यहां पूरा कराया जा चुका है। शीघ्र ही अन्य क्षेत्र में भी इस कार्य को पूरा करा लिया जायेगा। इससे जहां विद्युत चोरी बन्द हुई, वहीं लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा प्राप्त होने के साथ ही दुर्घटना की संभावना भी समाप्त हो गयी है।

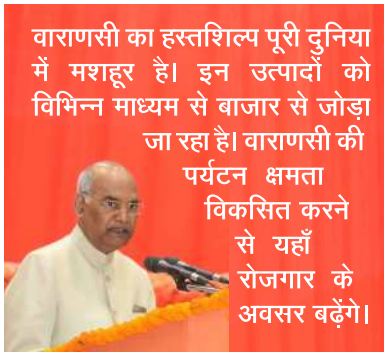

प्रधानमंत्री के प्रयासों से विश्व पटल पर आया वाराणसी

राष्ट्रपति जी ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि वाराणसी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वाराणसी को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री सहित फ्रांस एवं जर्मनी के राष्ट्रध्यक्षों के आगमन से काशी का सम्मान पूरे विश्व में फैला है और इसी आकर्षण के कारण देश–विदेश से लोग यहां की संस्कृति, विरासत आदि को देखने हेतु खिंचे चले आते हैं।

अगले तीन वर्षों में 20 लाख युवाओं को मिलेंगे रोजगार

गांवों में छिपी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत 6 लाख से अधिक बच्चों का विभिन्न कोर्सों में इनरोलमेंट किया गया। 2.5 लाख बच्चे पासआउट हुए तथा एक लाख 40 हजार बच्चों को विभिन्न बड़ी–बड़ी कम्पनियों में प्लेसमेण्ट कराकर सेवायोजित कराया गया।

वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट से होगा रोजगार सृजन

वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट' योजना लागू की है। इसके लिये 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी बजट में किया गया है। इस योजना के तहत, हर जिले के वहां के किसी मशहूर उत्पाद को बाजार एवं हुनर को मंच प्रदान करने का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आगामी 03 वर्ष में 20 लाख नवयुवकों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

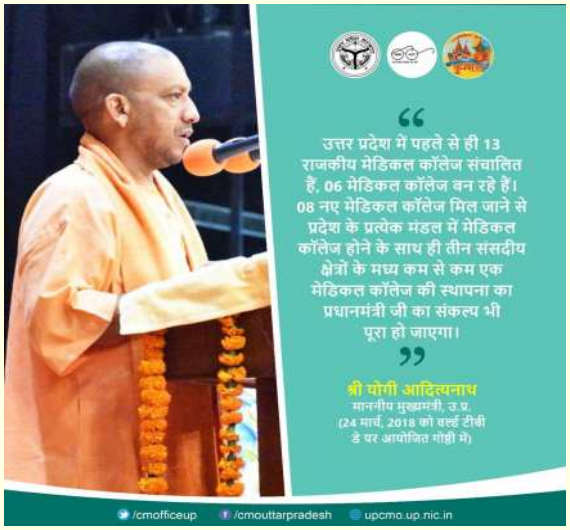

वन विभाग में 1088 पदों पर शीघ्र भर्तियां

सर्वाधिक 620 वन रक्षकों के पदों पर होंगी भर्तियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग के समस्त रिक्त पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत 846 पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और 242 पदों हेतु उप्र लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। रिक्त पदों में सर्वाधिक 620 पद वन रक्षकों कें हैं। वन विभाग की ओर से प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार 38 पद सहायक सांख्यिकी अनुभाग के, 39 पद मानचित्रकार, 37 पद सर्वेयर, 31 पद आशुलिपिक, 620 पद वन रक्षक तथा 81 पद वाहन चालकों के हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय वनाधिकारी अर्थात् रेंजर के 205 पदों तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 37 पदों पर भी भर्ती की कार्रवाई की जायेगी। लोक सेवा आयोग द्वारा रेंजर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा शेष पदों पर भी शीघ्र ही भर्तियां की जायेंगी।

विधानसभा से दोबारा पास हुआ यूपीकोका

संगठित अपराध आज अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है। जिस प्रकार से आज के युग में साइबर क्राइम का जाल फैलता जा रहा है और आतंकियों की फंडिग की जा रही है, उसके दृष्टिगत संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधानसभा में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक–2017 (यूपीकोका) पारित हो गया।

राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी हो जाएगा कानून

समय व परिस्थितियों की मांग के अनुरूप बनाये गये इस विधेयक को सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जायेगा। राज्यपाल इसे अनुमति हेतु महामहिम राष्ट्रपति को संदर्भित करेंगे और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यूपीकोका कानून प्रभावी हो जाएगा।

सुरक्षा प्रदान करेगा यूपीकोका

यूपीकोका का उपयोग केवल संगठित अपराधों जैसे माहौल खराब करने वालों, फिरौती, ठेके, अवैध खनन, वन कटान, नकली दवा, अवैध शराब व रंगदारी वसूलने वालों के खिलाफ ही किया जायेगा। इस कानून के लिए सरकार ने बेहतर प्रावधान किए हैं, जिससे इसके दुरूपयोग की कोई संभावना नहीं है।

मृत्यु दण्ड तक है सजा का प्रावधान

यूपीकोका में अपराधियों हेतु बेहद कड़ी सजा के प्रावधान हैं, जिसके अन्तर्गत सात वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। आरोपितों पर 15 से लेकर 25 लाख रूपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यूपीकोका आतंकी अतिविधियों में लिप्त अपराधियों से लेकर अन्य संगठित अपराध करने वाले अपराधियों पर प्रभावी होगा।

सेना और सैनिकों की सहायता को तत्पर सरकार

अशोक, शौर्य तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को उत्तर प्रदेश सरकार देगी आर्थिक सहयोग

1986 से पहले वीरता पदक पाने वाले जांबाजों को मिलेगा वार्षिक भत्ता

पूर्व सैनिकों के बेहतर इलाज के लिए पॉलीक्लीनिक निर्माण हेतु एक माह में भूमि हस्तांतरण के निर्देश

भारतीय सेना पर देश को गर्व है। भरतीय सेना ने अपने शौर्य व पराक्रम से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। सेना के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सेना से संबंधित प्रत्येक समस्या का समयबद्ध रूप से हल निकालने हेतु तत्पर है।

सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन में सैन्य अफसरों के साथ शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जांबांजों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए वीरता पुरस्कार की एकमुश्त धनराशि तथा वार्षिक राशि को बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 जनवरी, 1986 से पूर्व के अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र तथा अन्य वीरता पुरस्कार पाने वाले जांबांजों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा अन्य विशिष्ट पदक पाने वालों की पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी।

बढ़ेगी पुरस्कार राशि

परमवीर चक्र विजेताओं की पुरस्कार राशि 32.50 से बढ़ाकर 52 लाख रूपये प्रस्तावित है, जबकि महावीर चक्र तथा वीरचक्र की राशि क्रमशः 19.50 लाख तथा 13 लाख से बढ़ाकर 31 लाख तथा 20.80 लाख तक करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों में भी लगभग एक लाख रूपये तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है।

> **शहीदों की अंत्येष्टि में राज्य सरकार के प्रतिनिधि अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहेंगे और उनके परिवारजनों को प्रदान किया जाने वाला आर्थिक सहयोग भी उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा।**

शहीदों व दिव्यांग सैनिकों के परिवारीजनों को नौकरी का शासनादेश जारी

सैन्य आपरेशन के दौरान शहीद हुए तथा दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को 'डेथ इन हार्नेस' योजना के अन्तर्गत नौकरी प्रदान करने हेतु शासनादेश जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सैन्य अधिकारियों तथा पूर्व सैनिकों को स्टाम्प ड्यूटी में वर्तमान में प्रदान की जा रही छूट की सीमा बढाने और सेवारत सैनिकों हेतु भी इसे लागू किये जाने पर विचार चल रहा है। ■

फिरोजाबाद के कांच उद्योग को बढ़ावा देगी सरकार

रोजगार के नये अवसर

फिरोजाबाद का कांच उद्योग अपनी अनूठी कला हेतु सुप्रसिद्ध है। यहां के उद्यमियों ने अपने कौशल से जनपद फिरोजाबाद की कार्य कुशलता को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में कांच उद्योग को शामिल करके राज्य सरकार इसके विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। इन्वेस्टर्स समिट में जनपद के कांच उद्योगपतियों द्वारा 833 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनके क्रियान्वयन से इस उद्योग की तस्वीर बदलेगी और रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन होगा, जिससे बड़े पैमाने पर युवा लाभान्वित होंगे।

कांच उद्योग के श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के अतिरिक्त राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों के लिए एक विशेष आवासीय विद्यालय बनाए जाने की कार्य योजना पर कार्य कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद फिरोजाबाद में 3448 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं 253.38 लाख रुपए की 17 योजनाओं का लोकार्पण करते हुए जनपद के सोफीपुर में 400 केवीए का विद्युत स्टेशन एवं आसफाबाद में ओवरब्रिज बनाए जाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री जी द्वारा 2000 लाभार्थियों को नवीन निर्मित शौचालय, 1000 महिला समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड के स्वीकृति पत्र, 2680 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाभी, 476 लाभार्थियों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का स्वीकृति पत्र, 500 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन नवीन स्वीकृति पत्र, 46 लाभार्थियों को व्यक्तिगत शादी अनुदान के स्वीकृति पत्र, 250 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के स्वीकृति पत्र तथा 1500 आशा बहुओं को मोबाइल वितरित कर लाभान्वित किया गया।

आलू किसानों को संरक्षण

जनपद फिरोजाबाद की दो विशेषताएं, एक यहां के उद्यमी और दूसरे यहां के किसान है। यहाँ के आलू उत्पादक किसानों ने विशिष्टता के माध्यम से दुनिया में अपनी अलग पहचान बनायी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है, परन्तु अभी तक उनके लिए कोई योजना नहीं थी। पहली बार वर्तमान सरकार द्वारा आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया गया। आलू उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आलू विकास बोर्ड का भी गठन किए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उनके संरक्षण के लिए एक बड़ी कार्य योजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है। जनपद में फसल ऋण मोचन योजना के माध्यम से लगभग 42 हजार किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गत एक वर्ष में उत्तर प्रदेश को नयी दिशा देने का प्रयास किया गया है। सरकार ने प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भयमुक्त वातावरण में रह सके।

टीबी रोगियों के लिए डॉट्स योजना

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टीबी रोगियों के उपचार के लिए संचालित डॉट्स योजना बहुत अच्छी है। इस योजना में निःशुल्क उपचार आदि की जानकारी रोगी को उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही, रोगी के परिवार को भी इस रोग के सम्बन्ध में जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। न्यूट्रीशन की कमी से जूझने वाला तबका इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा टीबी रोगियों के न्यूट्रीशन के लिए 500 रुपए प्रतिमाह की व्यवस्था सराहनीय है। टीबी के उपचार से सम्बन्धित सभी लोग इस रोग के उपचार के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा निःशुल्क दवा, न्यूट्रीशन के लिए धनराशि की व्यवस्था आदि को जन सामान्य तक पहुंचा रहे हैं।

टीबी हारेगा यूपी जीतेगा

पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से देश ने पोलियो उन्मूलन में सफलता प्राप्त की है। सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर वैसी ही सफलता टीबी उन्मूलन में भी प्राप्त की जा सकती है। दुनिया में एक करोड़ से अधिक टीबी रोगी हैं। इनमें से लगभग 27 प्रतिशत भारतवर्ष में हैं। उत्तर प्रदेश में भी टीबी रोगियों की संख्या काफी है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण टीबी उन्मूलन में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी बड़ी है।

मुख्यमंत्री जी ने 'विश्व क्षय रोग दिवस' पर आयोजित गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक देश से टीबी के उन्मूलन के प्रधानमंत्री जी के संकल्प की सिद्धि इस रोग के उपचार के सम्बन्ध में जन–जागरूकता और जन सहभागिता से ही सम्भव है। टीबी के उन्मूलन के लिए समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक शासन की सम्बन्धित योजनाओं को मिशन मोड में काम करके पहुंचाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

विश्व के टीबी रोगियों की संख्या का 27 से 30 प्रतिशत भारत में है। इसका 20 से 22 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। देश में प्रत्येक तीन मिनट में दो लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। टीबी का इलाज सम्भव है। राज्य सरकार टीबी मरीजों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव कदम उठा रही है। प्रदेश से टीबी के उन्मूलन के लिए सबको मिलजुल कर समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे टीबी हारे और प्रदेश जीते।

2 से 16 अप्रैल तक चलेगा जेई/एईएस जागरूकता अभियान

जेई/एईएस जागरूकता अभियान

राज्य सरकार 02 अप्रैल से 16 अप्रैल, 2018 तक जेई/एईएस के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनीसेफ के माध्यम से अभियान संचालित करने जा रही है। इस दौरान इस रोग से बचाव, उपचार और प्रदेश सरकार द्वारा उपचार के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी।

100 अतिरिक्त वेन्टीलेटर की व्यवस्था

जेई/एईएस के उपचार हेतु 100 अतिरिक्त वेन्टीलेटर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग इस कार्यक्रम का नोडल विभाग है। ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास आदि इस अभियान की सफलता के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य सरकार टेली कंसल्टेशन एवं टेली मेडिसिन की योजना पर भी काम कर रही है।

प्रदेश को मिले 8 नये मेडिकल कालेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में वायरोलॉजी सेण्टर की स्थापना तथा इस वर्ष प्रदेश में 08 नये मेडिकल कॉलेज देने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में पहले से ही 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, 6 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 8 नये मेडिकल कॉलेज मिल जाने से प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में मेडिकल कॉलेज होने के साथ ही तीन संसदीय क्षेत्रों के मध्य कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रधानमंत्री जी संकल्प पूरा हो जाएगा। ■

प्रोफेशनल्स तैयार करेगा 'यंग स्किल्ड इंडिया'

युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना प्रदेश सरकार का ध्येय है, इसे पूरा करने की राह में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने आईआईटी बीएचयू के साथ एक समझौता किया है, जिसके अन्तर्गत आईआईटी बीएचयू अपने यहां चलने वाले स्टार्ट अप 'यंग स्किल्ड इंडिया' के अन्तर्गत युवाओं को प्रोफेशनली हुनरमंद बनाएगा। इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश सरकार तथा आईआईटी बीएचयू के बीच इस संबंध में समझौता हुआ था।

युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

समझौते के अंतर्गत आईआईटी बीएचयू के मालवीय संवर्धन और नवप्रवर्तन केंद्र द्वारा युवाओं को दो माह तक पेशेवर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में होने वाले कैंपस सेलेक्शन में कंपनियां कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही हैं। इन कंपनियों में पेशेवर युवाओं को वरीयता दी जा रही है। तमाम युवा प्रोफेशनल कौशल की कमी के कारण बड़ी कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इस प्रशिक्षण से उनकी कमियां दूर की जा सकेंगी आर उनके बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

गोरखपुर को मिला नयी उड़ान को तोहफा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि वायु परिवहन के क्षेत्र में ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे आम आदमी भी हवाई सफर का आनंद ले सके। इसी क्रम में उन्होंने गोरखपुर–दिल्ली सेवा को हरी झण्डी दिखाकर एक नयी उड़ान का तोहफा दिया। गोरखपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने इसकी पहली उड़ान को हरी झण्डी दिखायी।

अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है गोरखपुर

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन की दृष्टि से गोरखपुर के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्पाइस जेट (सिटिंग कैपेसिटी 72) एटीआर की जगह अब स्पाइस जेट बोइंग 186 यात्रियों की क्षमता वाला विमान गोरखपुर से दिल्ली की उड़ान भरेगा। यह विमान गोरखपुर से दिल्ली की दूरी केवल 80 मिनट में तय करेगा।

कम किराये में आम आदमी कर सकेगा हवाई यात्रा

इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने से अब साधारण लोग भी गोरखपुर से दिल्ली के बीच हवाई यात्रा कर सकेंगे। बोइंग का किराया कम होने के कारण यह सपना साकार हुआ है।

पुष्टाहार की बार कोडिंग

उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने आंगनबाड़ी केन्दों में बंटने वाले पुष्टाहार पर बार कोडिंग की नई व्यवस्था प्रारंभ की है। इससे पुष्टाहार की कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। पुष्टाहार की सप्लाई में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए इसमें अलग–अलग रंग के पैकेट रखे गये हैं।

सीधे आंगनबाडी केन्द्रों तक पहुंचेगा पुष्टाहार

नई व्यवस्था के अनुसार पुष्टाहार अब बाल विकास परियोजना कार्यालय की जगह सीधे आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुंचाया जायेगा। पुष्टाहार के पैकेटों की बार कोडिंग से पता चल जायेगा कि कौन सा पैकेट किस आंगनबाड़ी केन्द्र का है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 27 मार्च 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

तीन वर्ष के लिए स्वीकृत हुई नई तबादला नीति

उत्तर प्रदेश में काफी समय से एक–एक वर्ष के लिए स्थानान्तरण नीति जारी की जाती रही है परन्तु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों की तैनानी में स्थायित्व का निर्णय लेते हुए एक साथ तीन वर्ष की नई तबादला नीति जारी कर दी है। अब हर वर्ष इसी नीति के अंतर्गत तबादले किये जायेंगे।

जिलों में तीन और मंडल में सात साल पूर्ण कर चुके अधिकारियों का होगा तबादला

नई नीति के अंतर्गत जो अधिकारी जिलों में तीन वर्ष अथवा मण्डल में सात वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनका स्थानान्तरण किया जायेगा। स्थानान्तरण की प्रक्रिया एक अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अधिकतम 20 प्रतिशत होंगे तबादले

इस नीति के अंतर्गत एक विभाग से अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही तबादले किये जायेंगे। यदि किसी योजना के कारण किसी विभाग द्वारा तबादला नीति के अंतर्गत छूट प्राप्त की जानी है, तो उसे 15 अप्रैल तक कार्मिक विभाग को अपना प्रस्ताव प्रेषित करना होगा।

5 लाख तक के कार्य पर ई–टेंडरिंग की अनिवार्यता समाप्त

उत्तर प्रदेश में अब पांच लाख रूपये तक के कार्य पर ई–टेंडरिग की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक यह सीमा केवल एक लाख थी। इमरजेन्सी में कराए गए दस लाख रूपये तक के कार्य ई–टेंडरिंग प्रक्रिया से मुक्त होंगे।

10 जिलों में सुधरेगी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था

आठ पिछड़े जिलों में सृजित सभी पदों पर नियुक्ति होगी

गोरखपुर में रामगढ़ ताल के निकट स्पोर्टस काम्पलेक्स बनेगा

सारनाथ का बुद्धा पार्क जुडेगा ईको टूरिज्म से

बुदेलखंड के निराश्रित पशुओं के लिए 10 करोड़ रूपये

जिलों में चलेंगी 70 मेडिकल मोबाइल यूनिट

प्रदेशवासियों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु पूरे प्रदेश में 170 मेडिकल मोबाइल यूनिटों का संचालन किया जायेगा। इस मोबाइल यूनिट में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स तथा लैब टेक्नीशियन उपस्थित होंगे। इन यूनिट्स के माध्यम से प्रतिदिन 10 हजार से अधिक मरीजों के इलाज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दो करोड़ हुई विधायक निधि

विकास कार्यो को गति प्रदान करने के लिए विधायक निधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। यह राशि अब तक डेढ़ करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है। विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्यो पर स्टेट जीएसटी भी कम किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विधायकों को 100–100 हैण्डपम्प प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी